(घ) प्रत्येक राज्य में, अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा से संबंधित विशेष उप-योजनाओं की सिफारिश करते हुए, अगली पंच वर्षीय योजना (1978–83) के दृष्टिकोण पर विचार करने के लिए, शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित शिक्षा व्यापक बनाने पर कार्यदल ने आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा को उन्नत करने के लिए यह रिपोर्ट दी कि विशेष कार्यक्रमों और सुविधाओं की उदार व्यवस्था के कारण आदिवासी क्षेत्रों में गैर-शिक्षण लागत काफी अधिक होगी। इसलिये यह सुझाव दिया गया कि प्रत्येक राज्य को आदिवासियों की प्रारंभिक शिक्षा के लिए केवल उनकी आबादी के अनुपात में नहीं बल्कि उनके बढ़े हुए महत्व को लेकर पर्याप्त धन की व्यवस्था करनी चाहिये।

विवरण

राज्यों में प्राइमरी स्कूलों के छात्रों से संबंधित प्रति व्यक्ति व्यय के संबंध में 26-3-1979 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने के लिए अतारांकित प्रश्न संख्या 4689 के (क) और (ख) भागों के उत्तर के साथ संलग्न किया जाने वाला विवरण।

प्राथमिक स्कूली छात्रों की प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक खर्च--1975-76

		रु०
1.	आंध्र प्रदेश	110.3
2.	असम	93.0
3.	बिहार	82.6
4.	गुजरात	127.8
5.	हरियाणा	107.4
6.	हिमाचल प्रदेश	185.1
7.	जम्मू व काश्मीर	146.8
8.	कर्नाटक	252.2
9.	केरल	157.5
10.	मध्य प्रदेश	109.6
11.	महाराष्ट्र	140.0
12.	मणिपुर	158.9
13.	मेघालय	61.7
14.	नागालैंड	175.1
15.	उड़ीसा	95.8
16.	पंजाब	113.5
17.	राजस्थान	120.0
18.	सिक्किम	280.2
19.	तमिलनाडु	117.5
20.	त्रिपुरा	138.1
21.	उत्तर प्रदेश	56.1
22.	पश्चिम बंगाल	66.1
23.	अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	414.6
24.	अरुणाचल प्रदेश	225.1
25.	चण्डीगढ़	218.7
26.	दादरा व नागर हवेली	189.9
27.	दिल्ली	182.1
28.	गोआ, दमन व दीव	156.7
29.	लक्षद्वीप	362.2
30.	मिजोरम	160.9
31.	पांडिचेरी	202.7
	भारत	95.5

राजस्थान में डेरी विकास के लिये केन्द्रीय अनुदान

4690. **श्री लालजी भाई** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में विभिन्न स्थानों पर डेरी विकास के लिये केन्द्रीय सरकार की बड़ी मात्रा में अनुदान देने की योजना है ;

(ख) क्या डेरी विकास कार्यक्रम के लिये अनेक देश भी वित्तीय और अन्य रूप से सहायता दे रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) राज्य योजना के अन्तर्गत तथा भारतीय डेरी निगम, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम और विश्व बैंक के अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ जैसी वित्तीय संस्थाओं की सहायता से राजस्थान में डेरी विकास के लिए अनेक परियोजनायें शुरू की गई हैं।

केन्द्रीय सरकार ने निम्नलिखित रूप से वित्तीय सहायता प्रदान की है :—

1.	आपरेशन फ्लड 1.	331.63 लाख रुपए
2.	विश्व बैंक की सहायता प्राप्त परियोजना के अंतर्गत	365.59 लाख रुपए

इसके अलावा, केन्द्रीय सरकार ने विशेष पशुधन उत्पादन कार्यक्रमों के लिए 174.626 लाख रुपये की रकम का प्रशासनिक अनुमोदन भी किया है।

इसके अलावा, छठी योजनावधि के दौरान 48.29 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश करने का विचार है, जो नीचे दिया गया है :—

क्रम सं०	परियोजना	वित्तीय स्रोत (करोड़ रु०)	
		भारत सरकार	संस्थागत
1.	विश्व बैंक परियोजना	11.16	22.13
2.	आपरेशन फ्लड-1	–	4.00
3.	सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम	4.00	–
4.	मरु विकास	6.00	–
5.	अन्य	–	1.00
	योग	21.16	27.13

इसके अलावा, केन्द्रीय सरकार आपरेशन फ्लड-2 के क्रियान्वयन के लिए भारतीय डेरी निगम के माध्यम से वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी। सहायता की धनराशि का निर्धारण राज्य तथा भारतीय डेरी निगम के बीच बातचीत के बाद किया जाएगा।

Working Women Hostels

4691. SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) how many working women hostels have been sanctioned in the country in the years 1977-78, 1978-79;

(b) how many were sanctioned in Punjab;

(c) what is the plan for the year 1979-80;

(d) whether there is any plan to cover Punjab in it; and

(e) if not, reasons why?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (SHRIMATI RENUKA DEVI BARKATAKI):

(a) 1977-78 . . 20 Hostels

1978-79 . . 30 Hostels

(b) 1977-78 . . 6 Hostels

1978 79 Nil

(c) and (d). A provision of Rs. 150 lakhs has been suggested for the year 1979-80. Proposals from Punjab as and when received will be considered along with others in accordance with the guidelines of the Scheme.

(e) Does not arise.

Maintenance of Air Conditioning Plants meant for Telecom Equipments

4692. SHRI RAJENDRA KUMAR SHARMA: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether the circle heads conference in Delhi experiences the opinion that maintenance of Air Conditioning Plants meant for Telecom. equipments which was handed over to civil wing during emergency should be transferred back to Telecom Managers;

(b) if so, what actions are being taken in this regard; and

(c) whether the expenditure incurred by the civil wing to maintain the Air Conditioning plants was less than that being incurred by the Telecom. wings and if not what action is being taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI): (a) The day to day maintenance of air conditioning plants is handed by the Telecom. Engineers. However, the 2nd line maintenance consisting of overhaul and special repairs has been entrusted to an air conditioning cell under the Civil Wing during November, 77.